देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 02.12.2025

समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- उच्चतम न्यायालय आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में फैसला सुनाएगा। कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की घोषणा की।
- सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल कर्मचारियों से जुड़े 'नो वर्क, नो पे' मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
- उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों को अब 'लोक भवन' के नाम से जाना जाएगा।
- प्रदेश का पहला जेन–जी डाकघर पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित अभियांत्रिकी संस्थान में शुरू हुआ।

बनभूलपुरा

उच्चतम न्यायालय आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले में अपना निर्णय सुनाएगा। सुनवाई के मद्देनज़र क्षेत्र में कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने बताया कि हल्द्वानी शहर के लिए विशेष यातायात डायवर्जन योजना तैयार की गई है, जो आज प्रातः 8 बजे से अपराह्न 9 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक पूरे जिले में सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों तथा गैर–जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

संस्कृत आयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में संस्कृत के उत्थान और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाएगा। वे हरिद्वार में "भारतीय ज्ञान परंपरा एवं वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान" विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा ने प्राचीन मानव सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सनातन संस्कृति और वैदिक काल के इतिहास को देखते हुए स्पष्ट है कि सभी वेद, पुराण और उपनिषद संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। उन्होंने संस्कृत को अनादि और अनंत बताते हुए कहा कि इसका इतना महत्व है कि इसे देववाणी भी कहा जाता है।

सैनिक कल्याण मंत्री

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने सैनिक कल्याण मंत्री को बताया कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को नो–वर्क नो–पे प्रकरण के आधार पर हटाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गंभीर चिंता व्याप्त है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए श्री जोशी ने मुद्दे के समाधान के लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा और इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

लोक भवन

उत्तराखंड के देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवनों का नाम अब 'लोक भवन' कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद राज्यपाल के सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार देहरादून और नैनीताल राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से आधिकारिक रूप से 'लोक भवन' हो गया है।

जेन–जी डाकघर

प्रदेश का पहला जेन–जी डाकघर पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित अभियांत्रिकी संस्थान में शुरू हुआ। तहसील पौड़ी के अन्तर्गत घुड़दौड़ी स्थित गोविन्द बल्लभ पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थापित यह जेन–जी डाकघर तकनीक और नवाचार की नई सोच से परिपूर्ण है। यह जेन–जी डाकघर पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक स्पर्श देता है।

जेन–जी डाकघर का शुभारंभ करते हुए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि भारतीय डाक सेवा न केवल देश की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, बल्कि आज भी यह जनता की जरूरतों के सबसे निकट और सबसे विश्वसनीय सेवाओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि जेन–जी डाकघर आधुनिक तकनीकों से लेस किया गया है। जेन–जी डाकघर के माध्यम से डाक विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के नए द्वार खोलेगा।

प्रशासन गांव की और अभियान

'प्रशासन गांव की ओर' अभियान के तहत उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सिंगुणी गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का अवलोकन किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने गांव के आंगनवाड़ी भवन का भी निरीक्षण किया और बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पोषणयुक्त आहार, खेल सामग्री और पाठ्य सामग्री की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता, छात्रों के लिए आधुनिक पुस्तकालय, सड़क और पेयजल सुविधा, तथा मंडी परिषद के लिए भूमि जैसी कई समस्याएँ उठाईं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

संसद के शीतकालीन सत्र की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है– हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस खबर के शीर्षक में लिखता है– संसद में एसआईआर पर रण– अमर उजाला पीएम मोदी के हवाले से लिखता है– संसद ड्रामा नारेबाजी नहीं, नीतियां बनाने की जगह है।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बॉबी पंवार से नौ घंटे तक की पूछताछ– हिन्दुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर हुए थे वायरल।

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, छावनी बना बनभूलपुरा, फ्लैग मार्च भी हुआ– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– रेलवे की 30 एकड़ भूमि पर 4 हजार 365 घरों का अतिक्रमण, आज होगा फैसला।

और उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा मानदेय– अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है– सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश के बाद शासन से आदेश जारी, देय अर्जित अवकाश में समायोजित की जाएगी हड़ताल की अवधि।